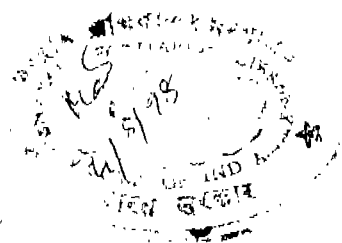


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 92 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 1998/वैशाख 4, 1920

No. 92 ]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 1998/VAISAKHA 4, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-7(आर. ई-98)/1997—2002

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1998

विषय : पुराने अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में वास्तविक चूक हेतु निर्यात दायित्व अवधि में एक-बारगी विस्तार।

फा. सं. 1/5/98-99-पी.सी II.—निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 4.11 के अंतर्गत महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत जारी अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित करते हैं :

- (1) मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जहां 31 मार्च, 1998 तक 100 प्रतिशत निर्यात पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, निर्यातों का एक हिस्सा निर्यात दायित्व अवधि की वैधता के बाद किया गया हो, अनुमोदित निर्यात अवधि के बाद किए गए निर्यातों के उस हिस्से के पोट पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर 5 प्रतिशत की समतुल्य राशि (अब के बाद इसे संयोजन शुल्क राशि कहा जाएगा) का भुगतान करने के बाद विनियमन प्रयोजन हेतु उक्त तारीख (31 मार्च 1998) तक निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की अनुमति होगी। संयोजन शुल्क केवल उन मामलों के वसूला जाएगा जहां सार्वजनिक सूचना संख्या-38/(पी एन)/1997-2002 दिनांक 1 सितम्बर, 1997 के अनुसार 5 प्रतिशत जुमाने का भुगतान नहीं किया गया था।
- (2) जहां तक इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख तक कोई निर्यात और/अथवा आयात नहीं किया गया है, लाइसेंस की निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (3) उन सभी मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में, जहां मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया हो, निर्यात दायित्व के बचे हुए पोट पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत के समतुल्य संयोजन शुल्क का भुगतान करके निर्यात दायित्व अवधि में 30 सितम्बर, 1998 तक के एक-बारगी अंतिम विस्तार की अनुमति है। निर्यात दायित्व अवधि (विस्तारित अवधि, यदि कोई हो समेत अथवा उसका कोई भाग) की समाप्ति की तारीख से प्रत्येक वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की दर से यह संयोजन शुल्क देय होगा।
- (4) मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में, जहां मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में कमी, लागू कुल निर्यात दायित्व के 15 प्रतिशत से अधिक है ऐसे लाइसेंसों को मात्र आधारित अग्रिम लाइसेंसों में परिवर्तित किया जा सकता है, और उसके बाद ऊपर (1) अथवा (3)

में उल्लिखित तरीके के अनुसार निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। यह लाभ उन मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में उपलब्ध नहीं होगा जहां नीति परिपत्र संख्या-8/97-98 दिनांक 1-7-97 के अनुसार माडवेट की व्यवस्था को उल्टा नहीं गया था। उन मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जहां मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में कमी लागू निर्यात दायित्व में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है, प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 (खण्ड-1) के पैरा 128(ख) (2)(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस की मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों में परिवर्तित किए बिना ऐसे लाइसेंसों को यथानुपात आधार पर बंद करने और विनियमन की अनुमति दी जा सकती है।

- (5) इस्पात उत्पादकों के मामले में जहां मानक निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों के अनुसार उप-समूह वाद अग्रिम लाइसेंस (मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस और मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस) जारी किए गए थे, जहां 31-3-98 तक निर्यात पूरा कर लिया गया था, वहां और अलग-अलग निविष्टि के संदर्भ में नहीं, बल्कि उप-समूह वाद अनुमत निविष्टियों के प्रति किए गए निर्यात तक यथा अनुपात आधार पर ऐसे लाइसेंसों को नियमित किया जा सकता है बशर्ते सम्बद्ध ब्रॉड-बैंड मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के अधीन निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन बनाये रखा गया हो। ऐसे मामलों में अनुमोदित निर्यात दायित्व की अवधि (बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, सहित) के बाहर आने वाले उस निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के भाग पर 5 प्रतिशत संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर विनियमन किया जायेगा। ऐसे लाइसेंसों के संबंध में भी जहाँ निर्यात दायित्व को पूरा करने में कमी हुई है, उपर्युक्त उप-पैरा (3) में बताये गये ढग से संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर निर्यात दायित्व की अवधि को 30 सितम्बर, 1998 तक बढ़ाया जा सकता है और इसके पश्चात् निर्यात पूरा होने पर, इस उप-पैरे में पहले दर्शाए गए अनुसार लाइसेंसों को नियमित किया जा सकता है।
- (6) उन लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी जहाँ गलत सूचना/धोखाधड़ी की जानकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को मिल गई हो कोई/या क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी/मुख्यालय, डी. जी. एफ. टी. के प्रवर्तन विंग द्वारा कोई प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की गई है। तथापि, निर्यात दायित्व पूरा करने में वास्तविक चूक संबंधी मामलों में मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि करने के बारे में विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जहाँ दण्डात्मक आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, वहाँ निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. निर्यात और आयात नीति/प्रक्रिया में निर्धारित दस्तावेजों के साथ मूल लाइसेंस और डी ई ई सी प्रस्तुत करने पर संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के तहत यथा अनुमेय निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार सीधे करने की अनुमति होगी।
3. यह सार्वजनिक सूचना, 31-3-96 तक शुल्क मुक्त स्कीम के तहत जारी अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में भी लागू होगी।
4. चूंकि यह केवल एक बार की छूट है जिसे अनुमति दी जा रही है इसलिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी दस्तावेजों तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी की जायें ताकि इस सार्वजनिक सूचना के अंतर्गत आने वाले मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बंद किया जा सके और निर्यातक को ऐसे मौका न मिल सके कि वह किसी देरी के लिए शिकायत कर सके और इन मामलों को बंद करने के लिए और समय न मांग सके। इस प्रयोजन के लिए, लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार का पृष्ठांकन लम्बित रखने पर निर्यातक को अनन्तिम आधार पर निर्यात करने की अनुमति दी जाये। ऐसे अनन्तिम निर्यात को लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस में निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार को पृष्ठांकित करने के बाद विनियमित किया जायेगा और इसकी डी ई ई सी बुक (भाग-2) में प्रविष्टि की जाएगी।
5. इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल,  
महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE**  
**PUBLIC NOTICE NO. PN 7 (RE-98) 1997-2002**  
New Delhi, the 24th April, 1998

**Subject : One-time extension in Export Obligation for bonafide default in respect of old Advance Licences.**

**F.No. 1/5/98-99/PC-II.**—In exercise of the powers under Paragraph 4.11 of Export and Import Policy, 1997-2002, the Director General of Foreign Trade makes the following arrangements in respect of Advance Licences issued under Duty Exemption Scheme :

- (i) In respect of Quantity Based Advance Licences, where 100% exports have already been completed upto 31st March, 1998, and part of exports have been effected outside the validity of the export obligation period, extension in export obligation period is allowed upto the said date (31st March, 1998) for regularisation purpose, on

payment of an amount (hereinafter referred to as composition fee) equivalent to 5% on that part of the F.O.B. value of exports which falls outside the approved export obligation period. The composition fee shall be recoverable only in respect of those cases where a penalty of 5% was not paid in terms of Public Notice No. 38/(PN)/1997—2002 dated 1st September, 1997;

- (ii) Where no export and/or import has been made till the date of issue of this Public Notice, no extension in export obligation period of licence will be allowed;
  - (iii) In respect of all Quantity Based Advance Licences, where at least 50% export obligation has been completed, either in terms of quantity or value or both, a one time final extension in the export obligation period is allowed up to 30th September, 1998 on payment of a composition fee equivalent to 5% of the unfulfilled F.O.B. value of export obligation. This composition fee of 5% shall be payable for each year reckoned from the date of expiry of the export obligation period (including extended export obligation period, if any) or part thereof;
  - (iv) In respect of the Value Based Advance Licences where shortfall in terms of quantity or value or both is more than 15% of the total export obligation imposed, such licences may be converted into Quantity Based Advance Licences, and thereafter, extension in export obligation period may be allowed in the manner indicated in (i) or (iii) above. This benefit shall not be available in respect of Value Based Advance Licences where reversal of MODVAT was not made in terms of Policy Circular No. 897-98 dated 1.7.1997. In respect of the Value Based Advance Licences where shortfall in export obligation in terms of quantity or value or both is not more than 15% pro-rata closure and regularisation of such licences may be allowed without converting Value Based Advance Licence into a Quantity Based Advance Licence as provided under Para 128 B (ii) of the Handbook of Procedures, 1992—97 (Vol. 1).
  - (v) In the case of Steel products, where special types of advance licences (QBAL and VABAL) had been issued sub-group wise as per Standard Input-Output Norms (that is, with quantity and/or value limits prescribed for each sub-group), where exports were completed upto 31.3.1998, such licences may be allowed to be regularised on prorata basis to the extent of exports made against the inputs allowed sub-group wise and not with reference to each and individual input, provided that the minimum value addition as was prescribed under the relevant broad-banded Standard Input-Output Norms is maintained. In such cases regularisation would be subject to payment of a composition fee of 5% on that part of the F.O.B. value of exports which falls outside the approved export obligation period (including extended period, if any), in respect of such licences also, where there is short fall in fulfillment of export obligation, extension in export obligation period is allowed up to 30th September, 1998 on payment of composition fee in the manner stated in sub-para (iii) above, and thereafter on completion of exports the licences may be regularised in the same manner as stated earlier in this sub-para.
  - (vi) No extension in export obligation period will be allowed in respect of the licences where misrepresentation/fraud has come to the notice of the Licensing Authorities and/or where any enforcement action has been initiated by Enforcement Wing of Regional Licensing Authority/Headquarters, DGFT. However, cases which relate to bonafide default in fulfillment of export obligation only, can be examined for considering export obligation period extension by the Advance Licensing Committee at Headquarters, Further, in respect of Advance Licences where adjudicating order has already been passed, no extension in export obligation period will be allowed.
2. Extension in export obligation period as admissible under this Public Notice shall be allowed directly by the Regional Licensing Authority concerned, upon submission of original licences and DEECs alongwith documents prescribed in the Exim Policy/Procedures.
  3. This Public Notice shall be applicable in respect of Advance Licences under the Duty Exemption Scheme issued upto 31.3.1996.
  4. As this is only a one time relaxation which is being allowed, all documentary and other formalities shall be completed by the concerned Regional Licensing Authorities of the DGFT as also by the Customs Authorities on top priority basis so that the cases covered by this Public Notice can be closed within the time prescribed and there is no occasion for the exporters to complain about any delay and seek further time for closure of these cases. For this purpose, the exporters should be allowed to make exports on a provisional basis pending endorsement of extension in export obligation period by the Licensing Authorities. Such provisional exports will be regularised and entered in the DEEC Book (Part. II) after extension in export obligation period is endorsed on the licence by the Licensing Authorities.
  5. This issues in the Public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

